



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2018/माघ 18, 1939

No. 55] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2018/MAGHA 18, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

प्रकरण सं. 01-3/2018

**विषय :** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लक्स यार्न" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की जांच की शुरुआत।

**फा सं.6/3/2018-डीजीएडी.**—मैसर्स जय श्री टेक्सटाइल्स (आदित्य विड़ला नुवो लि. की एक इकाई) (जिसे आगे याचिकाकर्ता/आवेदक' कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 70 ली काउंट से कम के फ्लक्स यार्न (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संगत सूचना के साथ एक आवेदन (जिसे आगे याचिका कहा गया है) दाखिल किया है।

## विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "70 ली काउंट (43 एनएम) से कम के फ्लक्स यार्न" हैं। 70 और अधिक ली के फ्लक्स यार्न को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। फ्लक्स यार्न एक 100 % लीनेन यार्न है। यह एक प्राकृतिक सेल्युलॉसिक फाइबर है जिसकी उच्च कंडक्टिविटी है।

3. वर्तमान जांच में पीयूसी के लिए माप की इकाई एमटी में वजन है। विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 53 के तहत एक विशेष एचएस कोड 5306 1090 और 5306 2090 है। हालांकि, आयात अन्य एचएस कोड के तहत भी हो सकता है, इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तथापि एचएस कोड केवल संकात्मक है और उत्पाद विवरण हर परिस्थितियों में प्रचलित रहेगा।

#### समान वस्तु

4. समान वस्तु के संबंध में नियम 2 (घ) इस प्रकार है :

*"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान न हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं;*

5. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। दोनों ही उत्पादों में भौतिक और रसायनिक गुणों, कार्यों व उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमतों, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसे मापदंडों के सन्दर्भ में तुलनीय गुण हैं। उपभोक्ता दोनों को ही एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और उपयोग कर रहे हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं।

6. इसीलिए इन्हें नियमों के तहत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' है।

#### घरेलू उद्योग और आधार

7. यह आवेदन मैसर्स जय श्री टैक्सटाइल्स (आदित्य बिड़ला नुवो लि. की एक इकाई) द्वारा दाखिल किया गया है जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। संबद्ध वस्तुओं के अन्य ज्ञात उत्पादकों में मैसर्स लिनेन आर्ट प्रा. लि., मैसर्स गोल्डन फाइबर्स, मैसर्स ए आई चम्पदानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं।

8. प्राधिकारी यह तय करते हैं कि याचिकाकर्ता के उत्पादन का समान वस्तु के सकल घरेलू में 'एक बड़ा हिस्सा' शामिल है। याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग है और यह याचिका कथित नियमावली के नियम 5 (3) के तहत आधार के मानदंड को पूरा करती है।

#### शामिल देश

9. वर्तमान जांच चीन जन. गण. ("संबद्ध देश" के रूप में उल्लिखित) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

#### सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध। के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाएगा।

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विषय देश के घरेलू बाजार में लागत और कीमतों के बारे में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए। विषय देश की विषय वस्तु के घरेलू मूल्यों पर सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता की अनुपस्थिति में, विषय देश के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है जो उत्पादन की लागत के आधार पर अनुमान लगाया गया है, घरेलू उद्योग के उपभोग मानदंडों के लिए। कच्चे माल और उपयोगिताओं, व्यवस्थित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और लाभ सहित समायोजित। के बाद घरेलू उद्योग के खपत मानकों पर विचार करते हुए उत्पाद की लागत के आधार पर उपलब्ध कराए गए निर्मित मूल्य के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार किया है।

12. तथापि प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करते समय उत्पादकों/ निर्यातकों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के निर्माण, उत्पादन और बिक्री तथा भारत में व अन्य देशों को निर्यात के संबंध में मौजूदा बाजार की स्थिति को दर्शाना होगा। इस उद्देश्य के लिए, निर्माता/निर्यातक, निम्नलिखित पर पर्याप्त जानकारी स्पष्ट और प्रदान कर सकता है:

- क. कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ. विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

### निर्यात कीमत

13. याचिकाकर्ता ने सीआईएफ स्तर पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य के आकलन के लिए द्वितीयक स्रोत अर्थात् इंपो ड्राइव से आयात संबंधी आंकड़ों को उपयोग करते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा व्यय, बन्दरगाह व्यय तथा बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है जिसे जांच प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान के अथवा डीजीसीआईएंडएस से डाटा की मांग करेंगे। साथ ही यदि आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और उनकी पुष्टि की जाती है तो प्राधिकारी निर्यातक के आंकड़ों पर भरोसा करना चाहेंगे।

### पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य की गणना कारखाना बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत के साथ तुलना करके की गई है। इस बात का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना बाह्य निर्यात कीमत से अधिक है जिसमें प्रथम दृष्टया इस बात का उल्लेख है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित की जा रही हैं। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक होने का अनुमान है और साथ ही संबद्ध देश के लिए अधिक भी है।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

15. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने निरपेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के रूप में और भारत में उत्पादन व खपत, कीमत में कटौती, कीमत अधिक्रमण, कम कीमत पर बिक्री के संबंध में कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। एक पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही 'सामग्री क्षति' के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

### पाटनरोधी जांच की शुरुआत

16. और यतः प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह पाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन ; घरेलू उद्योग को क्षति और पाटनरोधी आरंभ करने को न्यायोचित ठहराने के लिए कथित पाटन और मौजूदा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के तहत कथित पाटन और घरेलू उद्योग को इसके परिणामस्वरूप हुई क्षति की एक जांच आरंभ करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण हो सके और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा यह सिफारिश करना कि यदि लगाया गया तो क्या वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

### जांच की अवधि (पीओआई)

17. जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2017 है। तथापि क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 14 से मार्च, 15, अप्रैल, 15 से मार्च, 16, अप्रैल, 16 से मार्च, 17 और जांच की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।

**सूचना प्रस्तुत करना**

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग,  
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001  
Dgad.india@gov.in

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

**समय-सीमा**

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अधिसूचना के 2 सप्ताह के भीतर अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना हार्ड प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. यह नोट किया जाए कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **असहयोग**

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2018

Case No. OI/3/2018

**Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of 'Flax Yarn' originating in or exported from China PR.**

**F. No. 6/3/2018-DGAD.**— M/s. Jaya Shree Textiles (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.) (hereinafter referred to as the petitioner/applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as The Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as The Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Flax Yarn of below 70 Lea count (hereinafter referred to as the "subject goods") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

#### **Product under consideration**

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Flax Yarn of below 70 Lea Count (43 Nm)". Flax yarn of 70 and above lea is specifically excluded from the scope of the product under consideration. Flax Yarn is a 100% linen yarn. It is a natural cellulosic fiber with higher conductivity.

3. The unit of measurement for the PUC in the present investigation is weight in MT. The product under consideration is generally imported under HS code 5306 1090 and 5306 2090. However, import can also take place under other HS codes, therefore, it is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

#### **Like Article**

4. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

5. Petitioner has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & technical characteristics, product specifications, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

6. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

#### **Domestic Industry & Standing**

7. The Application has been filed by M/s. Jaya Shree Textiles (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.), who is the largest producer of the subject goods in India. The applicant has also submitted support letters from M/s Linen Art Pvt. Ltd., M/s Golden Fibers and M/s Raymond Luxury Cottons Ltd. who are the producers or are in the process of production of the subject goods.

8. The Authority examined the petition and after noting the total production of the subject goods in India, found that the production of the petitioner accounts for "a major proportion" in the total Indian production of the product under consideration, thus the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the AD Rules.

#### **Country involved**

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the "subject country").

#### **Normal Value**

10. Petitioner has claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

11. The petitioner has submitted that efforts were made to get information/evidence about cost and prices of subject goods in the domestic market of the subject country. In the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject country, the Normal value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production, considering consumption norms of the domestic industry for raw material and utilities, duly adjusted including selling, general and administrative expenses and profit. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject country on the basis of constructed values as made available by the petitioner for the purpose of this initiation.

12. However, while submitting the questionnaire response producers/exporters may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacturing, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- a. Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
- b. Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
- c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

#### **Export Price**

13. The petitioner has determined export price using import data from secondary source, i.e Info drive, to assess the volume and value of imports of subject goods in India. Price adjustments have been claimed on account of commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges, which has been accepted for the purpose of initiation. The Authority will call for the data from DGCI&S during the course of investigation. Also the Authority would like to rely on data of exporter in case the same are furnished and verified in the course of investigation.

#### **Dumping Margin**

14. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de minimis and also substantial for the subject country.

**Injury and Causal Link**

15. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

**Initiation of anti-dumping investigations**

16. And whereas, Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Period of Investigation**

17. The period of investigation (POI) is from 1<sup>st</sup> October 2016 to 30<sup>th</sup> September 2017. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16, Apr'16-Mar'17 and the period of investigation will be considered.

**Submission of Information**

18. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,  
New Delhi -110001.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

**Time Limit**

20. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

**Submission of information on confidential basis**

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

24. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of public file**

28. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority